Corex technology for Iron

*443. DR. SANJAYA SINH: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a State-owned Austrian firm has offered! to Indian firms its latest Corex technolo gy for Iron-making;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what are the names of the Indian firms with whom negotiations have been carried out and the agreements likely to be signed?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) Yes, Madam.

(b) and (c) The COREX Process is an alternate route for manufacture of pig iron. The pig iron industry is dfe-licensed and also qualifies for automatic Approval from Reserve Bank of India for grant of Foreign Collaboration under certain conditions. One of the entrepreneurs, namely M/s: Po-wmex Ispat Limited, Hyderabad has informed that they have signed a MOU with M/s. Voest-Alpine Industri-canlagenbau (VAI), Austria for adoption of Corex Technology for mnau-facture of pig iron.

मसूरी के हरे-भरे क्षेत्र का विनाश

@*447. **श्रीमती सत्या बहिन :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मसूरी के हरे-भरे क्षेत्र को नष्ट करके वहां कंकरीट का जंगल बनाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस विध्वंस को रोकने का विचार रखती है ;

(ग) इस प्रकार कितने क्षेत्र की हरियाली नष्ट की गई है और साथ ही इस विनाश का कितने लोगों पर असर पड़ा है ; और

(घ) क्या सरकार ने इन निर्माणों को स्वीकृति प्रदान की थी, यदि हां तो प्राधिकृत और अप्राधिकृत निर्माणों की अलग-अलग संख्या कितनी है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) यह कहना तो ठीक नहीं है कि मसूरी के हरे-भरे क्षेत्र का विनाश हो रहा है, हां, यह अवश्य है कि हाल ही के वर्षों में मसूरी में काफी मात्रा में निर्माण गतिविधियां रही हैं ।

(ख) चूंकि, शहरी विकास राज्य का विषय है, इसलिए इस संबंध में कार्रवाई करना उत्तर प्रदेश सरकार का दायित्व है । उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट के अनुसार निर्माण के लिए सभी प्रकार की अनुमति मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 के प्राव-धानों के अंतर्गत नियमों के अनुसार दी जाती हैं । उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी बताया है कि चूना-पत्थर की खानों और खदानों को बन्द होने, परिवेशीय कार्य दल की स्थापना तथा वन विभाग के प्रयासों से मसूरी के आस-पास हरा-भरा क्षेत्र पुनः बहाल तथा विस्तृत हुआ है ।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि "उपलब्ध सूचना के अनुसार इस प्रकार विनष्ट हुए क्षेत्र तथा प्रभावित व्यक्तियों की संख्या नगण्य प्रतीत होती है" ।

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि विगत एक वर्ष के दौरान विभिन्न निर्माण गतिविधियों के लिए करीब 20 योजनायें अनुमोदित की गई हैं तथा अवैध निर्माणों के खिलाफ करीब 110 मामलों में कार्यवाही आरम्भ की गई है ।

@*पूर्वत: तारांकित प्रश्न 307, 29 जुलाई, 1992 से स्थानांतरित ।